



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2003/27 अगस्त, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 18 जुलाई, 2003

संख्या वि०स०-लैज-गवर्नमेंट बिल/1-69/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संवालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश साधारण विधायक (संशोधन) विधेयक, 2003 (2003

का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 18 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2003 का विधेयक संख्यांक 8.

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 23 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1968 का
24.

2. हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा-2 में, विद्यमान खण्ड (ठठठ) का लोप किया जाएगा। धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की विद्यमान धाराओं 3-क, 3-ख और 3-ग का लोप किया जाएगा। धारा 3-क, 3-ख और 3-ग का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 30 और 31 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां यह आता है, "वितायुक्त, हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 30 और 31 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 31-क का लोप किया जाएगा। धारा 31-क का लोप।

6. मूल अधिनियम की धारा 33 में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां यह आता है, "वितायुक्त, हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 33 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 33-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 33-क का अन्तःस्थापन।

"33-क. संक्रमणकालीन उपबन्ध.—मूल अधिनियम की धारा 30, 31 या 33 के अधीन, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को अधिकरण के समक्ष लम्बित किसी भी अपील या आवेदन को इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटारा जाएगा।"

धारा 40 का संशोधन। 8. मूल अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) का लोप धन। किया जाएगा।

निरसन और व्याप्ति। 9. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्व मूल अधिनियम की धारा 3-क के साथ पठित धारा 40 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम तथा अधिकरण की स्थापना और अधिकरण की सहायता के लिए पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी किसी भी अधिसूचना का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) हिमाचल प्रदेश सामान्य विचार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्- 2003 का 2 द्वारा निरसन किया जाता है।

(3) उप-धारा (2) के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 के अधीन अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों का शीघ्र न्यायनिर्णयन करने के उद्देश्य से 1999 में विक्रय कर अधिकरण स्थापित किया गया था। तथापि इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी क्योंकि अपील और पुनरीक्षण के न्यायनिर्णयन में इसकी गति धीमी ही नहीं थी अपितु इसके मामलों के निपटारे की संख्या, इस तथ्य के होते हुए भी बहुत अपर्याप्त थी कि प्रतिरिक्त पीठासीन अधिकारी केवल अपील और पुनरीक्षण के मामलों को निपटाने के लिए पूर्ण कालिक अधिकरण के रूप में कार्य कर रहा था। वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान केवल 92 मामलों का निपटारा किया गया जबकि 239 मामले संस्थित किए गए थे। इसके प्रतिरिक्त मामलों की इतनी कम संख्या के निपटारे पर 15.07 लाख रुपये का वार्षिक व्यय अधिकरण की वित्तीय रूप से बोझग्रस्त तस्वीर स्पष्टतया दर्शाता है। मामलों का अपर्याप्त संख्या में संस्थित होना, कम निपटारा और मामलों के लम्बित रहने के साथ-साथ सदृशपूर्वक अधिक लागत यह सब बातें विक्रय कर अधिकरण के बने रहने के विरुद्ध गई हैं। परिणामस्वरूप वित्तायुक्त (अपील) के, अधिक समुचित और आर्थिक रूप से हितकर तथा स्थापित संस्थान को अपील का कार्य सौंपने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए, कार्य की मात्रा के साथ संगत, अपील प्रशामन को सुप्रवाही बनाना और मितव्ययता के उपाय का भी सूत्रपात करना आवश्यक समझा गया था। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया था।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 का संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 2) 21 मई, 2003 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे 21 मई, 2003 के राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रमारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख....., 2003.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप राजकोष को लगभग 15 लाख रुपये की वार्षिक बचत होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख; 2003

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2003.

**THE HIMACHAL PRADESH GENERAL SALES TAX (AMENDMENT)
BILL, 2003**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Act, 2003.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 22nd day of May, 2003.

24 of 1968

2. In section 2 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), the existing clause (III) shall be omitted.

Amendment of section 2.

3. The existing sections 3-A, 3-B and 3-C of the principal Act shall be omitted.

Omission of sections 3-A, 3-B and 3-C.

4. In sections 30 and 31 of the principal Act, for the word "Tribunal", wherever it occurs, the words and sign "Financial Commissioner, Himachal Pradesh" shall be substituted.

Amendment of sections 30 and 31.

5. The existing section 31-A of the principal Act, shall be omitted.

Omission of section 31-A.

6. In section 33 of the principal Act, for the word "Tribunal", wherever it occurs, the words and sign "Financial Commissioner, Himachal Pradesh" shall be substituted.

Amendment of section 33.

7. After section 33 of the principal Act, the following new section 33-A shall be inserted, namely :—

Insertion of section 33-A.

"33-A. Transitional provisions.—Any appeal or application, under sections 30, 31 or 33 of the principal Act, pending before the Tribunal on the date immediately preceding the date of commencement of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Act, 2003 shall be disposed of in accordance with the provisions of the principal Act as amended by this Act."

Amend-
ment of
section 40.

8. In section 40 of the principal Act, in sub-section (2), clause (aa) shall be omitted.

Repeal and
saving.

9. (1) Any rule made, under clause (aa) of sub-section (2) of section 40 read with section 3-A of the principal Act, and any notification issued in relation to the establishment of the Tribunal and appointment of the Presiding Officer or any other officer to assist the Tribunal, immediately preceding the date of commencement of this Act are hereby repealed.

(2) The Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

(3) Notwithstanding such repeal under sub-section (2), anything done or any action taken under the repealed Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, the Sales Tax Tribunal was established in 1999 with the objective of speedy adjudication of appeals and revision cases. However, this basic objective could not be achieved because there was not only slow pace of adjudication of appeals and revisions but the disposal-quantum was also very inadequate despite the fact that the Presiding Officer was working as a whole-time Tribunal exclusively attending to appeals and revision cases. During the financial year 2002-2003, the disposal was only of 92 cases against institution of 239 cases. Besides this, the annual expenditure of Rs. 15.07 lakhs on disposal of such less number of cases clearly reflects a financially burdensome profile of the Tribunal. The inadequate institution of case work, less disposal, piling pendency and correspondingly high cost taken together weighed against the continuance of the Sales Tax Tribunal. Consequently, it was considered essential to streamline the appellate administration consistent with the volume of work and to introduce a measure of economy, by making alternative arrangements for assigning the appellate work to the more appropriate and economically advantageous and established institution of the Financial Commissioner (Appeals). This had necessitated immediate amendments in the Act *ibid*.

2. Since the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2003 (H. P. Ordinance No. 2 of 2003) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 21st May, 2003, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 22nd May, 2003. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

3. This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The 2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted will result in an annual saving of Rs. 15 lakh approximately to the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

**THE HIMACHAL PRADESH GENERAL SALES TAX (AMENDMENT)
BILL, 2003**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968).

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The..... 2003.